

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश के अनुपालन में सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन एवं विवेचना के डिजिटाइजेशन संबंधी



## पुलिस मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक-टीएस-सीसीटीएनएस-65 / 2012-(रिट 8835 / 2018) दिनांक: दिसम्बर 11, 2018  
सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।  
समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।  
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) उत्तर प्रदेश।  
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) उत्तर प्रदेश।  
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) उत्तर प्रदेश।

विषय:- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 30-10-2018, 15-11-2018, 29-11-2018 के अनुपालन में सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन एवं विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु सीसीटीएनएस पोर्टल के लिये निर्गत किये गये विभिन्न एसओपी0 एवं निर्देश विषयक।

ज्ञातव्य हो कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश दिनांक 30-10-2018, 15-11-2018, 29-11-2018 के अनुपालन में सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन एवं विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रचलित कार्यवाही के क्रम में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समांक पत्र दिनांक 14.11.2018 को जारी किये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 04.01.2019 को माननीय न्यायालय में आख्या प्रेषित किये जाने हेतु तिथि निर्धारित है।

2. सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस पोर्टल पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में विभिन्न SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं) उपलब्ध करायी गयी है:-

A. सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रचलित "11 डाटा बैंक सर्विसेज को अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं)" उपलब्ध कराये जाने विषयक।  
संलग्नक-ए

- B. सीसीटीएनएस पोर्टल पर हत्या, लूट, डकैती, फिरौती हेतु अपहरण, एससी/एसटी एक्ट, दहेज हत्या एवं बलात्कार के अपराधों की केस डायरी कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) की अनुसंधान माड्यूल (Investigation Module) पर सम्पादित की गयी विवेचना का विवरण।
- C. सीसीटीएनएस पोर्टल पर 24 फार्म उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में 16 अतिरिक्त फार्म अंकित करने हेतु। संलग्नक-सी
- D. सीसीटीएनएस पोर्टल पर विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) एवं फिंगर प्रिंट ब्यूरो (FPB) भेजे गए प्रदर्श का विवरण अंकित करने हेतु।
- E. सीसीटीएनएस पोर्टल पर सीसीटीएनएस पोर्टल गिरफ्तारी प्रपत्र IIF-3 के कुल 1,37,349 अपराध की सूची के कुल 2,12,613 अभियुक्तों की फोटो साइज 200 KB से कम एवं साफ एवं स्पष्ट खींचा हुआ कम्प्यूटर में एकत्रित फोटो को साफ्टवेयर पैच के माध्यम से अपलोड किये जाने हेतु।
- F. सीसीटीएनएस पोर्टल पर "अनुसन्धान से जुड़े फॉर्म को भरना एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड किये जाने हेतु निर्देश" फार्म अंकित करने हेतु।
- G. सीसीटीएनएस पोर्टल पर "लूट के मामलों के पंजीकरण में नये जोड़े गये मेजर हेड/ माइनर हेड पर्स छिनैती, चैन छिनैती एवं मोबाइल छिनैती में दर्ज किये जाने हेतु निर्देश" अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज किया जाना।
- H. सीसीटीएनएस पोर्टल पर "संज्ञेय मामलों के अन्वेषण में अंतिम रिपोर्ट फार्म को भरना एवं मुकदमें का खात्मा या खारजी (expunge) की रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु निर्देश" अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज किया जाना।
- I. सीसीटीएनएस पोर्टल पर "प्राथमिकी दर्ज करते समय पीड़ित की सूचना" अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज किया जाना।
- J. सीसीटीएनएस योजना में कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 वर्जन में **Latitude and Longitude** से सम्बन्धित सूचना हेतु 'My GPS Coordinates' ऐप का उपयोग किया जाना।
- K. सीसीटीएनएस पोर्टल पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 वर्जन के माध्यम से पुलिस के समस्त प्रपत्रों एवं अन्य महत्ववूर्ण सूचना दर्ज किया जाना।
- L. सीसीटीएनएस पोर्टल हेतु सम्बन्धित बीट मैपिंग ऐप की ट्रायल 04 जनपद-लखनऊ, अमेठी, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद में प्रचलित है। यह ऐप अगले 01 सप्ताह में समस्त प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा। बीट मैपिंग लिंक ([https://ncog.gov.in/gps\\_data.apk](https://ncog.gov.in/gps_data.apk)) के माध्यम से Application डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर इन्स्टाल करके "बीट मैपिंग के लिए SOP के अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी बीट की सीमा का निर्धारण किया जाना।
- M. सीसीटीएनएस पोर्टल के अन्तर्गत OCIS में ऐसे अपराध जिसमें गिरोह बनाकर घटनायें की जा रही हैं उन अभियोगों की सम्बन्धित थाना प्रभारी तथा प्रभारी डी0सी0आर0बी0 द्वारा गिरोह के समस्त सदस्यों से सम्बन्धित सूचनायें शत-प्रतिशत दर्ज किया जाना।
- N. सीसीटीएनएस पोर्टल के अन्तर्गत प्राथमिकी देखें (View-FIR) व्यवस्था के दृष्टिगत डीजी परिपत्र संख्या 75/2015 दिनांक 09.12.2015 का अनुपालन कराया जाना।
- O. सीसीटीएनएस पोर्टल पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा FIR, GD एवं CD के सन्दर्भ में पर्यवेक्षी टिप्पणी अंकित किया जाना।
- P. सीसीटीएनएस पोर्टल में जिला बदर व इनामी अपराधी/गुमशुदा व्यक्ति एवं अज्ञात शव के डाटा की सूचना अंकित किया जाना/समस्त 1 से 24 फार्म/अभियोगों से सम्बन्धित ट्रायल के दौरान वादी और गवाहों, विवेचकों के सम्बन्ध में सम्मन/वारन्ट की सूचना/अन्य समस्त सूचनाओं को शत प्रतिशत दर्ज किया जाना।
- Q. मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 संख्या 2302/2017 में पारित आदेशों के क्रम में काइम सीन में विडियोग्राफी के प्रयोग के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के पत्र संख्या टीएस-04/2015 दिनांक

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश दिनांक 22.09.2018 अनुस्मारक पत्र 26.10.2018 का अनुपालन।

R. मुकदमा पंजीकृत किये जाने, एफआईआर, चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट, केस डायरी कटने पर, रिकवरी, एफएसएल को प्रदर्शों प्रेषित किये जाने पर वादी एवं पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकारी अधिकारी को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा निर्देशित किया गया है कि आई०ओ० का नाम, मोबाइल नम्बर, थाना, जनपद का नाम का एसएमएस मैसैज भेजने की व्यवस्था अगले 07 दिवस में लागू कर दी जायेगी, जिसका अनुपालन किया जाय।

S. UPCOP मोबाइल ऐप, Performance Measurement System App (PMS) का अनुपालन किया जाय।

3. उपरोक्त याचिका संख्या: 8835/2018 में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रपत्रों की प्रति सुलभ संदर्भ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

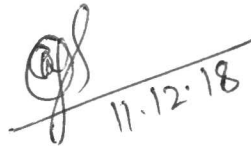
क्र०सं०	संदर्भ का विवरण	संलग्नक
1	BAIL No. 8835 of 2018 Order 30-10-2018	A
2	BAIL No. 8835 of 2018 Order 15-11-2018	B
3	BAIL No. 8835 of 2018 Order 29-11-2018	C
4	टीएस—सीसीटीएनएस—65/2012(3616) दिनांक: 14-11-2018	D

4. जनपदों हेतु मा० उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ०प्र० सरकार में पारित निर्देश के अन्तर्गत प्रिन्टर/टोनर/पेपर इत्यादि हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु सीसीटीएनएस के बजट में विवेचना के लिए डिजिटाइजेशन फण्ड सहित नये बजट प्राविधान को निर्धारित किया गया है। जिससे थाने को प्रिन्टर/टोनर/पेपर उपलब्ध कराये जायेंगे।

5. उपरोक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर निर्गत निर्देशों के क्रियान्वयन की गम्भीरता से प्रति सप्ताह समीक्षा करें जिसकी माह दिसम्बर में प्रगति की आख्या पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश एवं माननीय न्यायालय में प्रेषित की जानी है।

6. उपरोक्त क्रम में मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों को भी चिन्हित कर प्रेषित करें।

संलग्नक: यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।

  
(ओ०पी०सिंह)  
पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जी०एस०ओ०, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. दिग्विजय, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड—ए, उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड—ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
5. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

### डाटा बैंक सर्विसेज संलग्नक-ए

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1-सामान्य ग्राम सूचना        | 7-वरिष्ठ नागरिक सूचना,             |
| 2-ग्राम अपराध विवरण,         | 8-एकल महिला जानकारी,               |
| 3-कैदी विवरण,                | 9-दवा गप्पी सूचना ,                |
| 4-रिट याचिका विवरण,          | 10-सेक्स अपराधी,                   |
| 5-हथियार लाइसेंस के विवरण,   | 11-पुलिस सूचना के लिए सहायक नागरिक |
| 6-गोलीबारी / लाठीचार्ज विवरण |                                    |

### 16 अतिरिक्त फार्म संलग्नक-सी

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1-शिकायत,                     | 9-आपराधिक फाइल,  |
| 2-आग हादसा,                   | 10-प्रकरण प्रगति रिपोर्ट,                              |
| 3-मरे हुए जानवर/शव,           | 11-उद्घोषित अपराधी,                                    |
| 4-व्यक्तिगत खोज ज्ञापन,       | 12-फिंगर प्रिंट विश्लेषण,                              |
| 5-जमानत विवरण,                | 13-सम्मन/वारंट,  |
| 6-पूछताछ प्रपत्र,             | 14-कोर्ट ट्रायल विवरण,                                 |
| 7-प्रकरण दैनिकी विवरण जोड़ें, | 15-जेल का विवरण,                                       |
| 8-रिमांड प्रपत्र,             | 16-सम्पत्ति के मालखाना से रिलीज के लिए कोर्ट में आवेदन |

### CCTNS CAS 24 FORMS

1	First information Report(IIF-1)
2	Crime details form(IIF-2)
3	Arrest/Court Surrender Form(IIF-iii)
4	Property Search & Seizure Form(IIf-iv)
5	Final form / Report(IIf-v)
6	Court Disposal form(IIf-vi)
7	Result of Appeal Form(IIF-vii)
8	Missing Person Registration (IIf-VIII)
9	Unidentified Person Registration (IIIF-IX)
10	Registration of Unidentified Dead Body (IIF-X)
11	Registration of Unnatural Death (IIF-XI)
12	Gang Profile Form (OCIS-1)
13	Gang/Organization Criminal Activity Details (OCIS-2)
14	Member Details Form (OCIS-3)
15	General Diary
16	Non-Cognizable Offence Information Report
17	Lost Property Registration
18	Unclaimed/Abandoned Property
19	Medico legal Case Request Form (MLC)
20	Stranger Roll Registration
21	Preventive Action Registration
22	Foreigner Registration Form
23	C-Form
24	Missing Cattle Registration



Court No. - 13

Case :- BAIL No. - 8835 of 2018

**Applicant :-** Ravi

**Opposite Party :-** State Of U.P.

**Counsel for Applicant :-** Atul Verma, Akhilendra Pratap Singh

**Counsel for Opposite Party :-** G.A.

Hon'ble Attau Rahman Masoodi, J.

Sri Sujaanveer Singh, Director General Prosecution, U.P. is present in person.

The difficulty noticed in the present case is with respect to the transcription of case diary by the Investigating Officers in an illegible manner. The case diaries are largely indecipherable and illegible. Once the case diary in such a form is filed in the criminal proceedings, the courts due to the very form of document placed on record face difficulty in comprehending and evaluating the truth and the proceedings are thus delayed. There is every likelihood of inconsistency creeping in when the very material collected by the Investigating Officers in their handwriting is scribbled and cramped and on asking to be made legible by the prosecution or defence, the discrepancy may become quite obvious.

The investigation is a primary duty of the investigating agency, therefore, legible and correct copies of the material collected during the course of investigation inclusive of the medical reports are bound to be filed by the investigating officers so as to project a clear picture of the prosecution case in order to maintain transparency. It is suggested by the Officer present in the Court that if a certified true typed copy of the case diary and evidences is filed at the stage of filing the charge sheet, it would serve the purpose of law. However, for implementing such a mechanism, it is informed that the Director General of Police is competent to issue necessary circulars or guidelines in this behalf.

In these circumstances, it is directed that the Director General of Police be present in the court

to suggest as to the manner in which such a difficulty can be handled. Issuance of necessary circular in this regard may also be considered by the Director General of Police so that necessary mechanism to serve the purpose of law is put in place. The direction if carried out can be apprised through some responsible officer on the date fixed.

List this case on 15.11.2018. On the date fixed, the Director General of Police or any responsible officer on his behalf shall be present before this Court to assist on the issue and apprise.

**Order Date :-** 30.10.2018

Shahnaz

**Court No. - 13****Case :-** BAIL No. - 8835 of 2018**Applicant :-** Ravi**Opposite Party :-** State Of U.P.**Counsel for Applicant :-** Atul Verma, Akhilendra Pratap Singh**Counsel for Opposite Party :-** G.A.**Hon'ble Attau Rahman Masoodi, J.**

- 1- Circular dated 1.8.2017 filed today, is taken on record.
- 2- Heard, learned Counsel for the applicant and Sri Vinod Kumar Sahi, learned Addl. Advocate General, assisted by Sri S.N. Tilhari, learned AGA for the State.
- 3- Sri Ashutosh Pandey Additional Director General Technical Services U.P. Lucknow, is present in person. It is a welcome step on the part of Director General of Police, U.P. Lucknow, to issue a circular dated 14.11.2018 whereby the case diaries drawn during the course of investigation have now been directed to be made available on the portal of U.P. Police Department i.e. C.C.T.N.S. (Crime and Criminal Tracking Network System) in the background of orders passed by this Court. However, mere issuance of such a circular would serve no purpose unless the requisite budget is sanctioned by the State Government against the head of investigation. It is rightly pointed out by the Officer present in the Court that investigation is a cumbersome process. The transparency in the working of investigating agency as expected under various judicial orders to serve the administration of justice would necessarily require updation of requisite infrastructure. The infrastructure in the present case means equipments like printers, toners, paper, generators as well as Computer Operators. At present, there are 1533 police stations working in rural and urban areas of the State of U.P. In urban

areas wherever required, more than one Computer Operator is deployed whereas in rural areas at least one Computer Operator is available at each police station to upload a minimum of 7 forms out of 24 prescribed for various type of investigations. These 7 forms include FIRs, General Investigation, Arrest Memos, Recovery Memos, Charge-sheets, Final Reports and Court related forms prescribed under the procedural law. The availability of digital information in respect of other forms though not less important is incapable of being implemented until necessary infrastructure duly set up is made available to the Investigating Agency.

4- The necessary infrastructure as mentioned above inclusive of the additional strength of Computer Operators is essential without which the services are unworkable. In nutshell unless the State Government comes forward with a definite decision to provide requisite infrastructure to the Investigating Agency, issuance of directions or circulars would be meaningless. This aspect of the matter is to be dealt with by the State Government i.e. Home Department in consultation with the Department of Finance at the cabinet level. Independence of investigation and transparency is one of the vital dimensions of administration of criminal justice. Therefore, it is desirable that Principal Secretary, Home may be directed to forward necessary instructions as to how digitization of police investigation is possible and how such an object can be carried out to serve the purpose of law. Learned Addl. Advocate General Sri V.K. Shahi is directed to obtain necessary instructions on this aspect of the matter and call the officers in person for necessary assistance from the Home Department as well as Finance. The officer present today shall also appear.

5- This Court may also take note that in some matters directions were issued for installation of C.C.T.V. Cameras in the police stations. It is informed that out of 1533 police stations, C.C.T.V. cameras have been installed in 1048 police stations. For the rest of 485 police stations, tenders have been invited for installation of C.C.T.V. cameras. By the next date fixed, necessary instructions in this regard may also be made available.

6- The Court may further note that the postmortem reports except in Ghazipur district are not uploaded on the official web-site i.e. CCTNS. On the next date of listing the Court would also require assistance of the Principal Secretary, Home to apprise the Court as to how such computerized postmortem reports can be generated through computers in the whole of U.P. and as to how the difficulties in this regard may be overcome upon.

7- On the next date of listing, the Court would consider the aspect of separate budget to be made available to the investigation wing of the Police Department in order to facilitate its working freely in a well equipped culture.

8- The Court would also consider the need of a monitoring committee that may be in place to effectuate the results. A copy of this order may also be forwarded to the **Chief Secretary**, Government of U.P., forthwith who is expected to place the matter at the apex level in the meanwhile.

9- List this case on **29.11.2018**.

**Order Date :- 15.11.2018**  
Jyoti/Fahim

Court No. - 13

Case :- BAIL No. - 8835 of 2018

Applicant :- Ravi

Opposite Party :- State Of U.P.

Counsel for Applicant :- Atul Verma, Akhilendra Pratap Singh

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Attau Rahman Masoodi, J.

A copy of the G.O. dated 27.11.2018 is taken on record.

Pursuant to the order passed by this Court on 15.11.2018, the matter was taken up before this Court today when the Officers from the Home Department as well as the Department of Finance, U.P. are present.

Sri S.P. Upadhyaya, Special Secretary, Home, Sri O.P. Dwivedi, Special Secretary, Finance, Sri Ashutosh Pandey, Additional Director General, Technical Services, U.P. Police and Sri Haricharan Singh, Finance Controller, U.P. Police Department are present alongwith the respective Review Officers.

Sri Vinod Kumar Shahi, learned AAG assisted by Sri S.N. Tilhari, learned counsel at the very outset have informed that by G.O. dated 27.11.2018 issued by the Principal Secretary, U.P. Health Department, U.P. all the postmortem reports relating to police cases drawn in each district within the State of U.P. are now made available on-line, which service was previously restricted to district Ghazipur alone. It may be reiterated that by a previous circular issued on 14.11.2018, the case diaries were brought within the digitization process and directed to be made available on-line in order to cater the object of transparency in the matter of



investigation. It has been informed that the deficiency of staff i.e. computer operators has also been considered by the State Government and the process of recruitment is to commence from the third week of December, 2018.

The State Government has already taken a decision to recruit adequate number of Computer Operators so as to be deployed at all the police stations in order to deal with the on-line services effectively which consequently will give an impetus to the conclusion of investigation promptly and in turn, the criminal administration justice in a state governed by rule of law would maintain public trust intact. The decision by the State Government as regards the recruitment of necessary staff is a welcome step and this Court would appreciate such a measure.

Now coming to the aspect of expenditure, this Court has been informed that necessary expenditure is allocated to the police department against two Heads i.e. Head No. 42 and 47.

Head No. 42 is classified for the miscellaneous expenditure whereas Head No. 47 is for computer maintenance and stationery.

Special Secretary to the Finance Department is present in the Court who has stated that there is no administrative difficulty insofar as the sanction of budget for investigation is concerned. For this purpose, however, it is for the Police Department to make an assessment of the expenditure against Head No. 47 inclusive of the expenditure to be incurred for purchase of toners, stationery, maintenance or supply of necessary system equipments.

For the present all the expenditure claimed by U.P. Police Department has been sanctioned without any delay but in order to streamline the transfer of necessary expenditure, an assessment deserves to be made at the level of Additional Director General, Technical Services, U.P. Police who after collecting the data from all the police stations would arrive at a composite figure of expenditure and a proposal accordingly may be forwarded to the Department of Finance through Home Department. This exercise shall be undertaken by Sri Ashutosh Pandey, Additional Director General, Technical Services within a period of two weeks from today and the estimate so arrived at may be forwarded to the Principal Secretary, Home, who in turn shall forward the same to U.P. Finance Department without any further delay. The modalities of sanction/transfer shall be decided by the Department of Finance in consultation with the Home Department and the procedure settled therefor between the two departments may be apprised to this Court by filing an affidavit not later than a period of four weeks from today.

The Additional Director General, Technical Services, U.P., Lucknow is also permitted to identify a head against the Investigation from the expenditure allocated to C.C.T.N.S fund and any expenditure incurred against the said head shall be open to be audited by the Finance Department of which the periodic reports on quarterly basis shall be forwarded through the office of Additional Director General, Technical Services to the Finance Department routed through the Secretariat of Principal Secretary, Home U.P.

The aforesaid mechanism necessarily requires a regular monitoring by constituting a Monitoring Committee and this

Court would expect the Principal Secretary, Home and Additional Director General Technical Services, U.P. Police as well as the Principal Secretary Finance to propose a team of personnel who may be entrusted with the monitoring of digitization process and the performance of personnel deployed at the respective police stations. While proposing the monitoring team, the services of the competent advocates working on the State side is also open to be identified and utilized subject to the approval of this Court.

List this case on 4.1.2019 for further hearing.

The officers present today shall appear again on the next date of listing.

**Order Date :- 29.11.2018**

Fahim/-



# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक:टीएस-सीसीटीएनएस-65-2012

दिनांक:नवम्बर 14, 2018

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 में दिनांक 30.10.2018 को यह निर्णय पारित किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से यह अपेक्षा की गयी है कि वह एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित कर क्रियान्वित कराये जिसमें जनपदीय न्यायालय में प्रेषित की जाने वाली केस डायरी एवं अन्य साक्ष्यों की टाइप की गयी प्रमाणित प्रति सम्बन्धित न्यायालय में भेजी जाए। यह व्यवस्था विधिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। स्वहस्तलेख में लिखित केस डायरी व अन्य साक्ष्य सामान्यतया अपठनीय होते हैं।

2- ज्ञातव्य हो कि इस संदर्भ में वर्ष 2013 से उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर सीसीटीएनएस योजना प्रचलित है, जिसमें प्रदेश के सभी 1533 थानों में उक्त सीसीटीएनएस व्यवस्था लागू कर दी गई है एवं सभी थानों के पर्यवेक्षक अधिकारियों को समुचित हार्डवेयर प्रदान कर दिए गए हैं। सभी थानों पर कम्प्यूटर आपरेटर नियुक्त हैं, जो सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत 01 से 24 तक विभिन्न प्रकार के फार्म को भरते हैं एवं थाने के सीसीटीएनएस से सम्बन्धित अन्य कार्य भी करते हैं।

जी0डी0, प्रथम सूचना रिपोर्ट, गिरफ्तारी, बरामदगी एवं आरोप पत्र व अन्तिम रिपोर्ट सीसीटीएनएस योजना की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था (कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर) के माध्यम से अपलोड हो रहे हैं एवं उनका कम्प्यूटर जनित प्रिंट आउट माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

उपरोक्त व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावी करने के लिए बजट की आवश्यकता होगी परन्तु वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से ही मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का यथासम्भव अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जाए-

(1) सभी विवेचकों को निर्देशित किया जाए कि प्रथम चरण में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती हेतु अपहरण, एससी/एसटी एक्ट, दहेज हत्या एवं बलात्कार के अपराधों की केस

डायरी सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत थानों पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के अनुसंधान माड्यूल से करना सुनिश्चित करें।

(2) सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित विवेचकों को भी एक समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर कम्प्यूटर पर टाइप करने का जनपद स्तर पर पूर्व से स्थापित जनपद प्रशिक्षण केन्द्र (DTC) में प्रशिक्षण देकर उन्हें भी इस कार्य में दक्ष कराया जाए।

(3) जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा प्रत्येक अपराध गोष्ठी/आदेश कक्ष (O.R.) में इसकी समीक्षा की जाए।

(4) सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत विवेचना सम्बन्धी कार्यों के लिए एक विवेचक मोबाइल एप्प (IO App) विकसित किया जा रहा है जो 06 माह में क्रियान्वित हो जाएगा।

(5) मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र एवं बरामदगी प्रपत्र भरने एवं नक्शा नजरी व अन्य फोटो लेने के लिए इस वर्ष 4 करोड़ की धमराशि से करीब 1100 मोबाइल डाटा टर्मिनल (MDT) डिवाइस खरीदे जा रहे हैं। इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जा चुका है।

(6) जनपद गाजीपुर में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था द्वारा जारी की जा रही है। ऐसी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जा सकती है।

(7) पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों एवं पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पुलिस उप निरीक्षकों के लिए हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट कम्प्यूटर टाइपिंग की अर्हता परीक्षा नियत करने के लिए पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

(8) विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पठनीय रिपोर्ट के लिए अलग से सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत एफएसएल मॉड्यूल विकसित कर लिया गया है जो वर्तमान में कार्य कर रहा है तथा इससे उ०प्र० की चारों विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ जुड़ी हुई हैं।

उक्त योजना क्रियान्वित करने के लिए अपने-अपने सर्किल में क्षेत्राधिकारियों को नोडल आफिसर बनाया जाता है।

  
14.11.18

(ओ०पी० सिंह)  
पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अमुपालन सुनिश्चित कराने हेतु—

- 1— समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 2— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।

प्रतिलिपि: अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Court No. - 11

Case :- BAIL No. - 8835 of 2018

Applicant :- Ravi

Opposite Party :- State Of U.P.

Counsel for Applicant :- Atul Verma/Akhilendra Pratap Singh

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Ataul Rahman Maqsood, J.

Sri Sujaanveer Singh, Director General  
Prosecution, U.P. is present in person.

The difficulty noticed in the present case is with respect to the transcription of case diary by the Investigating Officers in an illegible manner. The case diaries are largely indecipherable and illegible. Once the case diary in such a form is filed in the criminal proceedings, the courts due to the very form of document placed on record face difficulty in comprehending and evaluating the truth and the proceedings are thus delayed. There is every likelihood of inconsistency creeping in when the very material collected by the Investigating Officers in their handwriting is scribbled and cramped and on asking to be made legible by the prosecution or defence, the discrepancy may become quite obvious.

The investigation is a primary duty of the investigating agency, therefore, legible and correct copies of the material collected during the course of investigation inclusive of the medical reports are bound to be filed by the investigating officers so as to project a clear picture of the prosecution case in order to maintain transparency. It is suggested by the Officer present in the Court that if a certified true typed copy of the case diary and evidences is filed at the stage of filing the charge sheet, it would serve the purpose of law. However, for implementing such a mechanism, it is informed that the Director General of Police is competent to issue necessary circulars or guidelines in this behalf.

In these circumstances, it is directed that the Director General of Police be present in the court



to suggest as to the manner in which such a difficulty can be handled. Issuance of necessary circular in this regard may also be considered by the Director General of Police so that necessary mechanism to serve the purpose of law is put in place. The direction if carried out can be apprised through some responsible officer on the date fixed.

List this case on 15.11.2018. On the date fixed, the Director General of Police or any responsible officer on his behalf shall be present before this Court to assist on the issue and apprise.

Order Date :- 30.10.2018

Shahbaz



Q12 :- (Instructions)

- (ग) आन्तरिक परीक्षण :-

- परिचय :-

- AS Fish Pond  
MEDICAL CENTER  
POSTMASTER HOUSE  
GRANDP

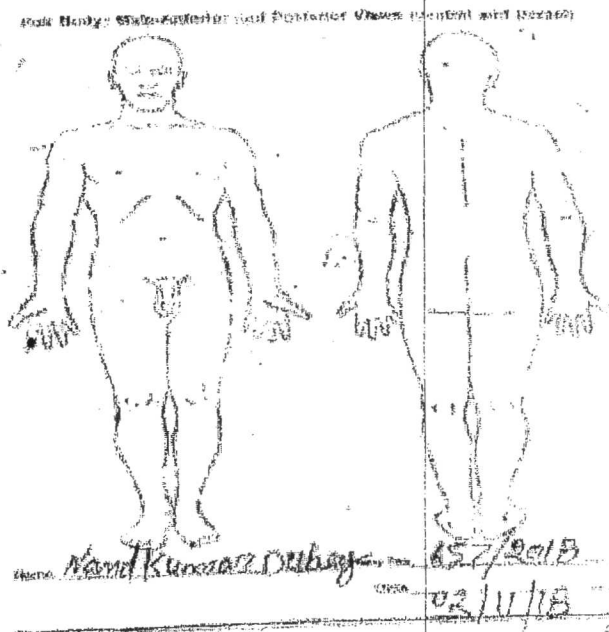
चिकित्साधिकारी का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर

Ashia & Kai

INCL 7704075202

RECEIVED

जे- मृतक का नाम- N. AND K. DUBEY.  
 मा- पुत्र/पुत्री/पत्नी- SIO-LATE PRADUMMAN DUBEY.  
 प- पता- VILL.-MAINPUR, PS-KARANDA, DISTRICT- CHAZIPUR  
 प- खत- 42, बख



Ashish Rai

MEDICAL OFFICER  
PORTMORTEN HOUSE  
GHAZIPUR